



कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योगों की चुनौतियों का विशलेषणात्मक अध्ययन

रामदेव गुर्जर

(बी.ए., एल.एल.बी., एल.एल.एम.) शोध विद्यार्थी, भगवन्त विष्वविद्यालय अजमेर (राजस्थान)

डॉ. दुष्यन्त कुमार

विधि विभाग (सहायक आचार्य)

ABSTRACT:

KEYWORDS:

1. भूमिका :-

भारत देश विश्व का एक मात्र देश है जहां अधिकाधिक कृषि भूमि पर आधारित है कृषि पर निर्भर रहकर ही उद्योग का विकास होना सम्भव है देश में जब कृषि का विकास होगा या कृषि उत्पाद अधिक उपलब्ध होंगे, जिन के प्रयोग के लिये उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे। देश का एक भाग जहां पर उत्पाद कम हो वहां भोजन के लिये यातायात तथा ढुलाई की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक अनाज को संभालने के लिये गोदामों की आवश्यकता पड़ेगी। कृषि के साथ जुड़े कुछ उद्योग चीनी उद्योग, पटसन, शोलेर उद्योग, कपड़ा उद्योग, पौलर तेल निकालने वाले कारखाने आदि इस तरह कृषि विकास उद्योगों के विकास में योगदान डालेंगे, परन्तु कृषि का विकास होता रहे इसलिये कृषि में कुछ उत्पादों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ट्रैक्टर उद्योग, मशीनरी, खाद, कीटनाशक आदि रसायनों से सम्बन्धित उद्योग जिनके उत्पाद कृषि में प्रयोग होते हैं भारत में प्रत्यक्ष तौर पर 54: मजदूर कृषि में लगे हुये हैं भारत का कुल कृषि निर्यात 42 बिलियन डालर है। कृषि आधारित उद्योग देश के भीतर और बाहर प्रतिस्पर्धी लाभ की धारणा के अनुरूप हैं व अधिपेश ग्रामीण श्रम को रोजगार प्रदान करने के लिए एक सुरक्षा कवच की भूमिका निभा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, प्रचलन रोजगार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यहां वास्तविक चुनौती यह है कि सरकार अपनी योजनाबद्ध और नीतिगत हस्तक्षेप को कितने प्रभावी ढंग से लागू करती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सामाजिक, आर्थिक संरचना, कृषि उत्पादन प्रणाली और बुनियादी कृषि विनिर्माण विषयताओं की पहचान को कम किये बिना सर्वांगीण औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों ने हमेशा न केवल उत्पाद आर उत्पादकता वृद्धि के माध्यम बल्कि प्रसंस्करण और विनिर्माण के माध्यम से कृषि उत्पादों में प्रणालीगत मूल्य संबंधन द्वारा की आय बढ़ाने की वकालत की है भारत की विषाल जनसंख्या अभी भी कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों में लगी हुई है भारतीय किसान काफी हद तक असंगठित हैं वे अपने विपणन योग्य अधिपेश के निपटाने के लिये बहारी एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीगत सम्पत्ति की बाजी के कारण उन्हें बिचोलियों/कमीशन एजेंटों को अपनी उपज के लिये मजबूर होना पड़ता है। प्राथमिक कृषि उत्पादन से कम आय और प्रसंस्करण तथा कृषि मूल्य श्रृंखला में निवेश की कमी के कारण कृषि के मुनाफे में तेजी से कमी आई है एवं कृषि कार्य गम्भीर दबाव में आ गया है इसी प्रकार औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने देश के परम्परागत उद्योगों को तहस-नहस कर दिया ब्रिटिश सरकार ने न तो बनाने का कोई प्रयास और न ही उनके स्थान पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना के लिये कोई ठोस कदम उठाये यही नहीं सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्रणाली, पूंजी, वित्त जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था में भी सक्रिय भाग नहीं लिया यहां तक की सरकारी खरीद के सिल-सिले में भी भारतीय उद्योगों को छोड़कर ब्रिटिश (विदेशी) उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती थी ऐसी परिस्थितियों में देश में आधुनिक उद्योगों का विकास संभव नहीं था आज भारत में कृषि उद्योग सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। जिसके द्वारा देश विकासशील से विकसित होने का प्रमाण सिद्ध कर सकता है देश का सर्वोत्तम विकास तभी संभव है जब तक कृषि व उद्योग का विकास नहीं होगा भारत का विकास संभव नहीं होगा।

2. कृषि आधारित उद्योग-परिभाषा और प्रकार :-

ग्रामीण क्षेत्रों और उनके आस-पास कृषि आधारित उद्योग का विकास कृषि को स्वीकार्य और आकर्षक बनाने तथा स्थिरता प्रदान करने की क्षमता रखता है "कृषि"

प्रो०ई०डब्ल्यू० जिम्मरमैन (E.W. Zimmermann) द्वारा लिखित बुक और "उद्योग" एक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है जिसमें विभिन्न औद्योगिक, प्रसंस्करण और विनिर्माण गतिविधियों का समावेश कृषि पर आधारित कच्चे माल पर होता है और उन गतिविधियों और सेवाओं को भी समाहित करता है जो इनपुट के रूप में कृषि से प्राप्त होती हैं कृषि और उद्योग किसी भी विकासशील राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में उनकी परस्पर निर्भरता और आपसी सम्बन्धों के कारण एक दुसरे के पूरक हैं कृषि उद्योग को इनपुट प्रदान करती हैं और औद्योगिक उत्पादन का उपयोग कृषि में इसके उत्पादन और उत्पादकता आधार का विस्तार करने के लिये किया जाता है इस प्रकार कृषि उद्योग न केवल कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करने वाली गतिविधियों को शामिल करता है बल्कि उन्हें भी शामिल करता है जो आधुनिक कृषि व्यवसाय के लिये इनपुट भी प्रदान करता है इनपुट-आउटपुट अनुबन्धन और कृषि व उद्योग एक दुसरे पर आधारित होने के कारण कृषि उद्योग दो प्रकार के हो सकते हैं। (क) प्रसंस्करण उद्योग या कृषि आधारित उद्योग (ख) इनपुट आपूर्ति उद्योग या कृषि उद्योग न इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि के लिये तैयार और विनिर्माण आदानों के माध्यम से कृषि समर्थन करने वाली एजेंसियों को कृषि उद्योग कहा जाता है जबकी कृषि आधारित उद्योग प्रक्रिया और मूल्य ऐसे कृषि संसाधनों को जोड़ते हैं जिनमें जमीन और पेड़-पौधे, फल-सब्जियाँ इत्यादी के साथ-साथ उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग पशुधन शामिल है अन्तराष्ट्रीय मानक उद्योगिक वर्गीकरण ढांचे के अनुसार कृषि आधारित उद्योग में से खाद्य और पेय, कपड़ा, जूते और परिधान, चमड़ा, रबर, कागज और लकड़ी, तम्बाकू उत्पादन के विनिर्माण/ प्रसंस्करण शामिल हैं।

रॉबर्ट हिल्सन ने अपनी पुस्तक बन्दजतल दवज कमअमसवच हतपबनसजनतम पदकनेजतल के अध्याय 4 के पृष्ठ संख्या 13 में अंकित है कि "किसी भी देश के उत्थान एवं आत्म निर्भरता के उद्योग विकसीत करना आवश्यक है जिससे आम नागरीक देश की अर्थव्यवस्था को प्रगतीशील बना सकें। भूमि उत्पादन की वृद्धि भी हो सके"

रॉबर्ट हिल्सन पुस्तक बन्दजतल दवज कमअमसवच हतपबनसजनतम पदकनेजतल

3. कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा क्यों?

भारत में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि, 20 कृषि जयवायु क्षेत्र और 15 प्रमुख जलवायु जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2001 में देश में कुल कृषकों की संख्या 12.73 करोड़ से घटकर 11.88 करोड़ कृषक रह गई है इस का कारण प्रसंस्करण और विनिर्माण के माध्यम से मूल्य संवर्धन अपव्यय में कमी और वृद्धिशील आप पर पर्याप्त ध्यान दिये बिना भारतीय कृषि का अत्यधिक उत्पादोन्मुखीकरण हो ना हो सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सैन्ट्रल इस्टीमेट्स ऑफ पोस्ट आर्वेस्ट इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी वर्ष 2015 की रिपोर्ट में "भारत में वस्तुओं और प्रमुख फसलों की कटाई और कटाई के उपरान्त होने वाली मात्रात्मक हानियों का आकलन" विषय से रिपोर्ट दी है रिपोर्ट के अनुसार कृषि जिनसों की कटाई और कटाई के बाद का नुकसान अनाज के लिये 4.65-5.99 प्रतिशत, दालों के लिये 6.36-8.41 प्रतिशत, तिलहन के लिये 3.08-9.96 प्रतिशत फलों के लिये 6.7-15.88

और सब्जियों के लिये 4.58–12.44 होते हैं मात्रात्मक नुकसान का कुल अनुमानित आर्थिक मूल्य 2014 की औसत वार्षिक कीमता पर 9651 करोड़ रुपये पाया गया, इस प्रकार नुकसान को काफी हद तक कम करने आधुनिक कृषि प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के संवर्धन और उसे अपनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में कृषि उद्योग की स्थापना करना समय की मांग है

कृषि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास का यही सही अवसर है क्योंकि शायद ही 2 से 3 प्रतिषत कृषि वस्तुओं का प्रसंस्करण किया जाता है भारतीय कृषि में मौजूदा मूल्यों में आ रही कमी की परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करना आवश्यक है ताकि उपयुक्त बुनियादी ढाँचे का विकास हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में तथा आस-पास के आधुनिक कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये निजी, सार्वजनिक भागीदारी को आकर्षित किया जा सके।

कृषि में नवाचार : समृद्धि की ओर बढ़ते कदम लेखक : डॉ. सुरेन्द्र कोठारी, डॉ एस.के. शर्मा, डॉ. रेखा व्यास

4. कृषि से उद्योगों की विशेषताएं :-

भारत में कृषि से उद्योग का विकसीत करने के लिए तीन श्रेणियों में बाटा जा सकता है (1) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों (2) चीनी, डेयरी, बेकरी, साल्टेड निकर्षण इकाइयों (3) कृषि : कृषि ओजार, बीज उद्योग, सिंचाई उपकरण, उर्वरक कीटनाशक आदि के मशीनीकरण को शामिल करने वाली कृषि इनपुट निर्माण इकाइयों तालिका-2 में उपलब्ध जानकारीयों की समीक्षा से, भारत के कृषि आधारित उद्योग की जटिल और विविधतापूर्ण को दर्शाया गया है, ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योग उत्पादन वितरण, विनिर्माण और विपणन चरणों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करते हैं तालिका-3 चुनिदा कृषि उद्योगों की प्रमुख विशेषताओं का परिक्षण करती है वर्ष 2017–2018 में कृषि आधारित उद्योगों का 45.3 प्रतिषत कुल शुद्ध मूल्य संवर्धन के लिये केवल 24.11 प्रतिषत साझा किया गया, भले की कुल श्रमिकों का 44.2 प्रतिषत इस क्षेत्र में लगे हुये थे इससे पता चलता है कि कृषि आधारित उद्योगिक परिदृश्य में स्थाई रूप से उपलब्ध संसाधनों और सरकार द्वारा विभिन्न सर्वसिद्धी-उन्मुख केन्द्रिय योजनाओं के माध्यम से किये गये प्रयासों के लाभों को पूरी तरह से भुनाया नहीं है वर्ष 2017–2018 में कुल 1.07 लाख कृषि आधारित उद्योगों में आसान मुद्दों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से हल करने से कृषि आधारित उद्योगों को अधिक दृष्ट्यमान और परिश्रमिक बनाने की एक बड़ी क्षमता है चुनिदा सरकारी पहल की समीक्षा।

(अ) खाद्य प्रसंस्करण और पेय पदार्थ :-

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और मूल्यवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न केन्द्रिय क्षेत्र की योजनाओं का लागू करता है इसने हाल ही में नई केन्द्रिय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के तहत अपनी योजनाओं को 2016–20 की अवधि के लिये रुपये 6000

जैविक कृषि में उद्यमिता विकास एवं रोजगार के अवसर, लेखक : रोशन चौधरी, डॉ अमित त्रिवेदी, डॉ हेमन्त स्वामी एवं डॉ. एस.के. शर्मा

करोड़ के आवंटन के पुनः संरचित किया है योजना में निम्नलिखित घटक सस्थापित किये गये हैं (अ) मेगा फूड पार्क (ब) एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्यवर्धित आधारभूत ढाँचा (स) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकता आधार मूल ढाँचा (द) मानव संसाधन विकास तथा संस्थाएं प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनाएं शामिल हैं कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए आधारभूत संरचना, विनिर्माण तथा खाद्य प्रसंस्करण संक्षण इकाइयों की स्थापना में सम्पूर्ण मूल्यों की श्रृंखला के लाभ मजबूत आधुनिक बुनियादी ढाँचा का निर्माण करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण और संक्षण क्षमता का निर्माण (विस्तार) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के घटक जैसे एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन आधारभूत ढाँचा एवं विनिर्माण और विपणन सुविधाओं का निर्माण, कृषि उत्पादन की कटाई और फसल के बाद के नुकसान को कम करने और ग्रामीण गैरकृषि क्षेत्र में परिश्रमिक आय और पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण है।

(ब) कपड़ा उद्योग :-

कपड़ा उद्योग को अत्यधिक रोजगार प्रदान करने वाला माना जाता है यह 4.5 करोड़ लोगों को सीधे और अन्य 6 करोड़ लोगों को सम्बद्ध क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी भी शामिल है भारतीय कपास, कपड़ा उद्योग काफी हद तक असंगठित है और उच्च उत्पादन तथा श्रम लागत से ग्रस्त है उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पुरानी होती मशीनरी कच्चे माल की गुणवत्ता और घरेलु व अन्तर्राष्ट्रिय बाजारों में मूल्यवर्धित कपास उत्पादों के लिये समुचित स्तर का अभाव वस्त्र उद्योग को विष्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और आधुनिकरण को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से सरकार नई योजनाबद्ध पहल की है जैसे कि एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना समुहबद्ध कार्य योजना, सामान्य सुविधा केन्द्र तथा संघोषित प्रौद्योगिकी उन्नयन नीधी योजना (पावरट्रेक्स) समर्थ कपड़ा उद्योग

क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना, व्यापक हथकरघा, समुह विकास योजना, राज्य और केन्द्र का कर और लेवी छुट जिससे उद्योग व कृषि बढ़ावा मिल सकें।

(स) जुट उद्योग :-

भारत में जुट उद्योग की स्थापित क्षमता 16.5 लाख मीट्रिकटन है, जिसमें से 11.5 लाख मेट्रीक टन जुट का उत्पादन होता है ऐसा अतिरिक्त क्षमता विपणन और आधुनिक तकनीक और उपकरणों को लाने का प्रयास किया है राष्ट्रीय जुट बोर्ड योजनाबद्ध हस्तक्षेप एवं अन्य बातों के साथ-साथ जुट मीलों को उनके मुद्दों और चुनौतियों को हल करने के लिये पंजीगत आर्थित सहायता प्रदान करता है।

(द) खादी और ग्रामोद्योग :-

देश में सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का खादी और ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न फसल उपरान्त कृषि और खाद्य आधारित सुक्ष्म उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देता है जैसे दालों और अनाज, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से खादी ग्रामोद्योग आयोग गैर-कृषि क्षेत्र में सुक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने को कोषित करता है जिससे अन्य बातों का समावेश है (1) कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (2) वन आधारित उद्योग (3) हस्त निर्मित कागजों और फाइबर, कपड़ा उद्योग आदि।

(ड) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन :-

रोजगार और आय सृजन क्षमता को ध्यान में रखते हुये, सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू करती है जैसा कि इस उपक्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये डेयरी गतिविधियों में डेयरी उद्यमिता विकास योजना, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष, डेयरी गतिविधियों व प्रबन्धन तथा मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन आधारभूत संरचना विकास निधि का समावेश।

5. कृषि आधारित उद्योग मुद्दों और समस्याओं की समीक्षा :-

कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में समान आय और रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित कराने के लिये अपनी उच्च क्षमता को बावजूद अविकसित रह गया है उपलब्ध जानकारीयों की समीक्षा/इंगित करती है कि भारत में कृषि आधारित

प्रो 0 डी0 हिटलसी के कथनानुसार

इकाइयों के प्रलंबित मुद्दों का समाधान किया जाना है जैसे कि वित्त, औद्योगिक नीति, अनुसंधान और विकास बुनियाद, सुविधाएं विपणन, उत्पादन और मानव संसाधन सम्बन्धी चिंताएं। तालिका-4 भारत में कृषि आधारित उद्योगों के समक्ष समस्याओं एवं सम्बद्ध प्रमुख मुद्दों को दर्शाया गया है भारत सरकार व राज्य सरकार में कृषि से सम्बन्धित योजनाओं में करोड़ों रुपये का बजट आने के बावजूद कृषि आधारित उद्योग विकसित नहीं हो रहे हैं जिसका प्रमुख कारण डवदवचवसल (एकाधिकार) है, एवं भष्ट नेताओं व अफसरों द्वारा भष्टाचार व गबन प्रवृत्ति के कारण विकास नहीं हो रहा है इस प्रक्रिया पर पूर्णतः रोक लगाकर धरातल स्तर पर योजनाओं का विकास करने हेतु आम आदमी को जागृत करे जिससे भावी योजना के तहत भारत देश विकासशील से विकसीत हो सके एवं नई तकनीकी सुलभ करवाकर आम कृषक को प्रेरित करने हेतु आयाम उत्पन्न करे एवं भारतीय योजनाकारों और नीति निर्माताओं ने हमेशा ग्रामीण और कृषि औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया है कृषि उद्योगों के निहित लाभ स्थानीय कृषि संसाधनों का अधिकतम उपयोग, बड़े पैमाने पर निवेश को जुटाना, बड़े-बड़े उद्योगपतियों विदेशी कम्पनीयों को सुलभ सुविधा देकर भारत में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करे एवं विष्व पैमाने पर प्रचार-प्रसार करे ताकि योजनाओं के अन्तर्गत सभी व्यक्ति, संस्था उद्योग स्थापित करने हेतु वातावरण प्रदान करें। रोजगार अवसरों का सृजन संकटपूर्ण ग्रामीण-षहरी प्रवास की रोकथाम, क्षेत्रों में असमानता में कमी लाना है इन उद्योगों में गांवों में प्रचार, लाभदायक व्यवसाय, गतिविधियों विविधिकरण के लिये एक विस्तृत, विष्वसनीय और टिकाऊ मॉडल पेप करने की क्षमता है। यह उद्योग मुद्दों तथा चुनौतियों से परे नहीं है सरकार विभिन्न

हाल ही में माननीय उपराष्ट्रपति एम0वेंकैया नायडू ने अपने एक संबोधन में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि ग्रामीण युवाओं के लिये रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकें। उन्होने संबद्ध

उपराष्ट्रपति एम0वेंकैया नायडू की पुस्तक ऑटोक्रैट से उद्धरित

गतिविधियों के साथ किसानों की आय बढ़ाने में कृषि-उद्योगों की भूमिका पर भी जोर दिया।

केन्द्रीय योजनाओं ड। ज़ाम् फ़ फ़क्क। (भारत निर्माण) स्टार्टअप इन्डिया जैसे नवीन प्रयासों के द्वारा अत्याधुनिक कृषि औद्योगिक आधारभूत संरचना सुनिश्चित करने की कोषित कर रहा है कृषि आधारित उद्योग देश के भीतर और बाहर प्रतिस्पर्धा लाभ की धारणा के अनुरूप है। वे अधिविषेष ग्रामीण श्रम को रोजगार प्रदान करने के लिये एक सुरक्षा कवच की भूमिका निभा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को योजनाओं लाभान्वित करके कृषि उद्योगों के लिये प्रोत्साहित करे एवं पिछड़े क्षेत्रों

का औद्योगिकरण, बिमार औद्योगिक इकाइयों का पुनः बहाल करना, अविष्कारों की प्रगति तथा आयात प्रतिस्थापित कर विदेशों से कच्चा माल तथा नई तकनीकी में आत्मनिर्भरता के लिये 1966 में आयात प्रतिस्थापन बोर्ड की स्थापना की गई जिससे केन्द्र सरकार इन योजनाओं का सुअवसर व राहत देश में अविष्कारों की प्रगति के लिये 1960 में अविष्कार उन्नति बोर्ड की स्थापना की गई परन्तु बजट व केन्द्र सरकार की उदासीनता के कारण विकास के आयम में औपचारिक गठन हो रहा है जबकि सरकार द्वारा बजट व ईमानदार प्रशासकों की नियुक्ति कर सुधारों रूप से आम जनता तक परिलाभ से जोड़ा जाना चाहिए। भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है इसके फल स्वरूप खेती काफी पिछड़ी हुई है उद्योग के विकास के कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम हो जायेगा इससे कृषि उद्योग का आकार बढेगा व खेती को अधिक उन्नति हो सकेगी। भारत को आत्मनिर्भरता के आयाम अपनाने चाहिए जिससे सभी वस्तुयें भारत में उत्पन्न होने लगेगी कृषि एवं उद्योग ही भारत में उत्पन्न होने लगेगी कृषि एवं उद्योग ही भारत देश को विकसीत करने में अहम योगदान हो सकता है जिस देश की कृषि उद्योग पिछड़ा ह उस देश में निर्धनता का प्रवेश हो जाता है जो निर्धनता उस देश को दीमक की तरह अन्दर से खोखला कर देती है एवं देश की आर्थिक स्थिति का ढांचा खोखला हो जाता है तब उस देश की आन्तरिक व बाह्य शक्ति शून्य हो जाती है।

कृषि के प्रमुख प्रकार:-

स्थानान्तरणशील कृषि, प्रारम्भिक स्थायी कृषि, व्यापारिक पशुपालन, चलवासी पशुपालन, चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि, चावल विहीन गहन निर्वाहन कृषि, व्यापारिक बागाती कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, व्यवस्थाव्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि, व्यापारिक शस्य व पशु उत्पादक कृषि, जीविकोपार्जन फसल व पशु उत्पादक कृषि, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि, विषिष्टीकृत उद्यान कृषि

पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा देशवासियों से मिले स्नेह-प्रेम के प्रति कृतज्ञ पंडित नेहरू जी ने अपनी वसीयत में लिखा था, कि मुझे भारत के लोगों ने इतना प्यार और स्नेह मिला है कि मैं इसका एक छोटा सा अंश भी उन्हें लौटा नहीं सकता और वास्तव में स्नेह जैसी मूल्यवान चीज के बदले में कुछ लौटाया भी नहीं जा सकता, उन्होंने लिखा कि मेरी राख का हिस्सा वतन को सपर्मित "मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए, यदि मेरी मृत्यु विदेश में होती है, तो मेरा दाह संस्कार वही कर दिया जाये और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए, इसमें से मुद्दीभर राख प्रयाग के संगम में बहा दी जाए जो हिन्दुस्तान के दामन को चूमते हुए समंदर में जा मिले, मेरी राख का ज्यादा हिस्सा हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखेर दी जाए, वो खेत जहाँ हजारों मेहनतकश ईसान काम में लगे हैं, ताकि मेरे वजूद का हर जरा वतन की खाक में मिलकर एक हो जाए, इस राख का कोई भी हिस्सा न ही बचाकर रखा जाए और न संरक्षित किया जाए"

पंडित जवाहर नेहरू जी द्वारा वसीयत में अपनी राख को खेतों में बिखरने हेतु लिखा गया है

REFERENCES

NO REFERENCES